भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 583
जिसका उत्तर बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

मूल्य निगरानी प्रणाली

583. श्री राहुल कस्वांः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में दालों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली दैनिक मूल्य निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत एक वर्ष के दौरान बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक सीमा, आयात नीतियों, बफर स्टॉक रिलीज आदि जैसे हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राजस्थान में दालों और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों के भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं और मिलों के विरुद्ध कोई जांच, छापे या स्टॉक ऑडिट किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दालें और तेल उपलब्ध कराने के लिए 'भारत दाल योजना', 'सस्ता तेल केंद्र' जैसी योजनाओं का राजस्थान में विस्तार करने की योजना बना रही है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर के 575 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों, जिनमें राजस्थान के 32 केंद्र भी शामिल हैं, द्वारा प्रस्तुत 38 खाद्य वस्तुओं, जिनमें दालें, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। दालों में, चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी की जाती है और खाद्य तेलों के मामले में, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पाम तेल के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी की जाती है।

(ख): जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, और उपभोक्ताओं की सामर्थ्य में सुधार करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 21 जून, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक तूर और चना पर स्टॉक सीमा लगा दी है। उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 'मुक्त' श्रेणी के तहत तूर और उड़द का आयात 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चना और मसूर के संबंध में 10% का आयात शुल्क लगाया गया है; और पीली मटर के आयात पर, इन दालों की कीमतों में पर्याप्त नरमी को देखते हुए 1 नवंबर, 2025 से 30% शुल्क लगाया गया है। 2024-25 के दौरान, बफर से दालों का स्टॉक खुले बाजार में बिक्री, राज्यों को उनकी कल्याणकारी स्कीमों के लिए आपूर्ति और भारत दाल तंत्र के जरिए खुदरा हस्तक्षेप के माध्यम से जारी किया गया है। भारत दाल तंत्र के तहत, बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारत दाल ब्रांड के तहत रियायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया गया।

खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने 30 मई, 2025 से कच्चे खाद्य तेलों (कच्चा सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल और कच्चा सूरजमुखी तेल) पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है, जिससे कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 16.5% (5% एआईडीसी सहित) हो गया है। रिफाइंड तेलों (रिफाइंड सोयाबीन, रिफाइंड पाम तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल) पर मूल सीमा शुल्क 32.5% पर स्थिर रखा गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है। कच्चे तेल पर आयात शुल्क कम करके खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से खाद्य तेलों की पहुँच लागत और खुदरा कीमतों में कमी आई है और साथ ही घरेलू तिलहन उत्पादन और रिफाइनिंग उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी विभिन्न पहलों और स्कीमों के माध्यम से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना, बर्बादी कम करना, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

(घ) और (ड.): व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों, बड़ी खुदरा विक्रेताओं जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक की निगरानी ऑनलाइन स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल के माध्यम से की जाती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा दालों के स्टॉक के प्रकटीकरण की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980 के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य तेलों पर हाल ही में आयात शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, एक ठोस प्रयास के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेल रिफाइनरियों का देशव्यापी निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। अधिकांश निरीक्षणित इकाइयों ने आयातित कच्चे खाद्य तेलों की लागत में कमी के कारण अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और वितरकों को दी जाने वाली कीमत (पीटीडी) दोनों को पहले ही कम कर दिया है, जो हाल ही में आयात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के कारण संभव हुआ है।

दालों की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2025 से भारत दाल व्यवस्था बंद कर दी गई है। वर्तमान में, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2025 तक (-) 5.02% के निम्न स्तर पर नियंत्रण में है। समग्र खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए, राजस्थान सहित देश भर के उपभोक्ताओं के लिए दालों और खाद्य योग्य तेलों में खुदरा हस्तक्षेप शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****